हरियाणा के सरकारी स्कूलों पर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

एक हालिया सरकारी रिपोर्ट से पता चला है कि राज्य में **19 स्कूल बिना किसी छात्र के हैं, 811 स्कूलों** में सिर्फ **एक शिक्षक** है और **कुल 3,148 स्कूलों में उनकी क्षमता के आधे से भी कम छात्र हैं।**

मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट, जिसमें फरवरी 2024 में **केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा** आयोजित एक बैठक के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया गया, जिसमें राज्य के 14,562 सरकारी स्कूलों को चिह्नित किया गया।
- रिपोर्ट ने विशेषकर प्राथमिक विद्यालयों में **शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या** पर प्रकाश डाला और सरकार को इन रिक्तियों को तुरंत भरने की सलाह दी।
- शिक्षकों की कमी का असर वेतन भुगतान के लिये **आवंटित केंद्रीय धनराशि** पर पड़ा है।
- प्राथमिक क्षेत्र में, वित्तीय सहायता वर्ष 2021-22 की अवधि में 19 लाख रुपए से घटकर 14 लाख रुपए हो गई है।
- इसी तरह, उच्च शिक्षा में कई रिक्त पदों के कारण अनुदान 20 लाख रुपए से घटकर 14 लाख रुपए हो गया है।
- रिपोर्ट में शिक्षकों की कमी के अलावा **इन स्कूलों में छात्रों के लिये बुनियादी ढाँचे की कमी** की भी बात कही गई है।
- जबकि स्कूल अतिरिक्त कक्षाओं के अपने लक्ष्य से 18% कम हैं, लड़कों और लड़कियों के लिये शौचालय 1% व 1.8% कम हैं। स्मार्ट क्लासरूम भी आवश्यक संख्या से 1.4% कम हैं।
- रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि अतीत की गैर-आवर्ती स्वीकृतियाँ, जिन पर वर्षों से राज्य द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, अंततः समग्र शिक्षा फ्रेमवर्क के अनुसार 5 वर्ष की अवधि के बाद राज्य की एकमात्र ज़िम्मेदारी बन जाएंगी।
- जिन स्कूलों ने सुविधाएँ स्थापित नहीं की हैं, उन्हें अपने प्रारंभिक प्रस्ताव वापस लेने चाहिये और नए प्रस्ताव के बारे में सोचना चाहिये।
- प्रस्तुत आँकड़ों में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिये राज्य सरकार को **लंबित कार्यों की प्रगति को नियमित रूप से** प्रबंध पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।

समग्र शिक्षा योजना

- यह **स्कूली शिक्षा के लिये एक एकीकृत योजना है, जिसमें प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा** तक की शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
- इसका उद्देश्य **समावेशी, न्यायसंगत और सुगम स्कूली शिक्षा** प्रदान करना है।
- यह 'सर्व शिक्षा अभियान' (SSA), '**राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान**' (RMSA) और '**शिक्षक शिक्षा**' (TE) की तीन योजनाओं को समाहित करती है।
- इस योजना में **1.16 मिलियन स्कूल,** 156 मिलियन से अधिक छात्र और सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.7 मिलियन शिक्षक (पूर्व-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक) शामिल हैं।
- इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। इसमें केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच वित्तपोषण में 60:40 का विभाजन शामिल है। इसे वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।

समग्र शिक्षा योजना 2.0

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer- DBT):**
    - योजना की प्रत्यक्ष पहुँच को बढ़ाने के लिये सभी **बाल-केंद्रित हस्तक्षेप छात्रों को सीधे सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफॉर्म** पर DBT मोड के माध्यम से समय-समय पर **शिक्षा का अधिकार** पात्रता के तहत पाठ्यपुस्तक, ड्रेस और परिवहन भत्ते प्रदान किये जाएंगे।
- **NEP की सिफारिशें:**
    - **भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन:**
        - इसमें **भाषा शिक्षकों** की नियुक्ति के लिये एक नया घटक है, जिसमें वेतन और प्रशिक्षण लागत के साथ-साथ द्विभाषी किताबें तथा शिक्षण सामग्री शामिल है, जैसा कि NEP में अनुशंसित किया गया है।

- **पूर्व प्राथमिक शिक्षा:**
  - इसमें अब शिक्षण एवं अधिगम सामग्री, स्वदेशी खिलौने और खेल तथा खेल-आधारित गतिविधियों के लिये **सरकारी स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक वर्गों को समर्थन देने के लिये वित्त प्रदान** करना शामिल होगा।
  - योजना के तहत पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों और आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लिये कुशल प्रशिक्षकों का समर्थन किया जाएगा।
- **निपुण भारत पहल:**
  - इस पहल के तहत शिक्षण सामग्री के लिये **प्रति छात्र 500 रुपए,** मैनुअल और संसाधनों के लिये प्रति शिक्षक 150 रुपए तथा आधारभूत **साक्षरता एवं अंकगणित के आकलन के लिये** प्रति ज़िले 10-20 लाख रुपए का **वार्षिक प्रावधान है।**
- **डिजिटल पहल:**
  - डिजिटल बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम और DTH चैनलों के लिये समर्थन सहित **ICT लैब तथा स्मार्ट क्लासरूम** का प्रावधान है, जो **कोविड-19 महामारी** के मद्देनज़र अधिक महत्त्वपूर्ण हो गए हैं।
- **स्कूल न जाने वाले बच्चों हेतु:**
  - इसमें 16 से 19 वर्ष की आयु के **स्कूली बच्चों को ओपन स्कूलिंग** के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने के लिये 2000 प्रति ग्रेड के वित्तपोषण का समर्थन देने का प्रावधान शामिल है।
  - स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों दोनों के लिये **कौशल तथा व्यावसायिक शिक्षा पर भी अधिक ध्यान** दिया जाएगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/report-on-haryana-government-schools